BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXV | 26th November 2014 | No. 17

सूबे में भी होगा बदलाव और विकास

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बोले केंद्रीय मंत्री रूडी

सम्मान समारोह को संबोधित करते माननीय केन्द्रीय सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्री श्री गिरिराज सिंह। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं माननीय केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी। बाँयीं ओर क्रमशः माननीय केन्द्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री श्री रामकृपाल यादव एवं चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कु. जैन।

गत 25 वर्षों में जहां कई उद्योगपति राज्य छोड़कर भाग गये वहां आप लोग अब भी टिके हुए हैं, इसके लिए मैं आपलोगों को सलाम करता हूँ। राज्य की स्थिति बदतर होती जा रही है। जहां देश में विकास की राजनीति चल रही है वहां इस राज्य में जाति की राजनीति चल रही है। आपलोग जब इतनी सहनशीलता के साथ आस पर टिके हैं तो एक साल और आस लगाये रहिये। यहां भी विकास का एजेंडा होगा और बदलाव आयेगा। यह बात केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने अपने सम्मान समारोह में कही। सम्मान समारोह बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इडस्ट्रीज ने दिनांक 15.11.2014 को चैम्बर प्रांगण में आयोजित किया था।

श्री रूडी ने कहा कि कई राज्यों में खपत से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। वहीं बिहार में 29 सौ मैगावाट का उत्पादन होता है। उद्योग के लिए जमीन व बिजली चाहिए। राज्य सरकार की लैंड बैंक योजना भी अधर में है। आज तक बिहार में एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्टेडियम, कन्वेंशन हॉल आदि नहीं बन सका। यहां सड़के टूटी हैं, गंदगी का अंबार है, नाले पर घर है, मास्टर प्लान की कोई योजना नहीं है। बिहार के छात्र बाहर जाकर बेहतर कर रहे हैं। पढ़ाई, व्यवसाय, उद्योग के लिए व्यवसायी बाहर जा रहे हैं। थोड़ा इंतजार करें, बदलाव आयेगा।

सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने इनपुट टैक्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे पेट्रोल की कीमत सात से आठ रुपये बढ़ गयी है। इस टैक्स के कारण कच्चा माल मंहगा हो गया है तो इससे सूक्ष्म व लघु उद्योगों को कठिनाई आयेगी ही। इस मुद्दे को उन्होंने मुख्यमंत्री व वित्त के समक्ष उठाया है। केंद्र सरकार राज्य के विकास में सहयोग करना चाहती है। आप समस्या बतायें और सभी तरह के उद्योगों की सूची पेश करें, केंद्र सरकार आपकी मदद करेगी। आपलोग प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के नारे में सहयोग करें। राज्य में उद्योग को लेकर केंद्र सरकार से बात की है। प्रधानमंत्री ने इस पर आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि सैमसंग कंपनी ने भारत में उद्योग लगाने का करार किया है, उसे बिहार में कैसे लाया जाये, इसके बारे में यहां के उद्योगपति एवं राज्य सरकार को काम करना होगा। इसमें केंद्र मदद करेगी।

केंद्रीय स्वच्छता व पेयजल मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना को देश का सबसे गंदा शहर बताया और कहा कि सफाई हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान व पेयजल योजना शुरू की है और विश्वास के साथ इसकी जिम्मेवारी हमें सौंपी है। इसे हम पूरा करेंगे और इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। वैसे पेयजल और स्वच्छता की नैतिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार इस मद में दिये गये धन का उपयोग भी नहीं करती है। केंद्र सरकार की योजना घर-घर सफाई करने की भी है। इसमें भी आमजन का सहयोग चाहिए। उन्होंने पेयजल पर कहा कि राज्य के 27 जिलों में प्रदूषित पेयजल मिल रहा है। आपलोग दो कदम सहयोग करें, केंद्र आगे चार कदम बढ़कर सहयोग करेगा। उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि वे 34 वर्षों से सामाजिक कार्य करते रहे हैं और कई बार सांसद भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री पद देकर अनुग्रहीत किया है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कृतज्ञ हैं।

इस मौके पर चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि अभी हमलोग सभी मंत्रियों के लिए सम्मान समारोह कर रहे हैं। सभी को परेशानियों से अवगत करा दिया जाएगा। अभी कौशल विकास मंत्री व लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्री भी बिहार से ही हैं और उन दोनों से यहां के उद्योग जगत को काफी अपेक्षाएं हैं। इनकी देखरेख में राज्य का उद्योग विकास करेगा।

कार्यक्रम में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, उपाध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, विधायक नितिन नवीन, अनिल कुमार व पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना के अलावे कई उद्योगपति मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष सुभाष कुमार परवारी ने किया। (साभार : राष्ट्रीय सहारा, 16.11.2014)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक के साथ चैम्बर में संवाद

स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजित सूद एवं महाप्रबंधक श्री अभिजीत दत्त। दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुजार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 13 नवम्बर 2014 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजित सूद के साथ चैम्बर के सदस्यों के साथ संवाद का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर स्टेट बैंक के पटना सर्किल के महाप्रबंधक (नेटवर्क-I) श्री अभिजीत दत्त, उप महाप्रबंधक श्री मनीष टंडन, उप महाप्रबंधक (एस०एम०ई०) श्री पी० नारायणन, क्षेत्रीय प्रबंधक (रीजन-I) के श्री दिव्यान्शु रंजन भी उपस्थित थे। चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

अपने स्वागत संबोधन के क्रम में चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बैंक की ओर से व्यापारियों को पूरी मदद मिले तभी बेहतर संबंध स्थापित होंगे। चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चैम्बर का संबंध काफी गहरा रहा है। उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक को चैम्बर द्वारा नि:शुल्क चलाये जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बैंक से संबंधित व्यवसायियों को हो रही कठिनाईयों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी समर्पित किया।

इस अवसर पर पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद सिंह ने श्री सूद को बैंक की अनक्लेम्ड मनी के विभिन्न आयामों के विधिक दृष्टिकोण से अवगत कराया और कई मुद्दों पर बैंक की प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त कई सदस्यों ने भी अपनी समस्याएँ रखी।

मुख्य महाप्रबंधक श्री अजित सूद ने ज्ञापन के बिन्दुओं और सदस्यों की बातें सुनने के बाद कहा कि एस०बी०आई० वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पटना में इलेक्ट्रोनिक शाखा खोलेगा। सभी काम इलेक्ट्रोनिक तरीके से होगा। इस शाखा में ग्राहक बैंकिंग कार्य खुद कर सकेंगे। इसमें कैश डिपॉजिट मशीन, एटीएम, पासबुक अपडेट मशीन, ई-के०वाई०सी०, इंटरनेट बैंकिंग समेत कई काम ग्राहक खुद कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर ही बैंक के स्टाफ ग्राहकों की मदद करेंगे। इलेक्ट्रोनिक ब्रॉच मार्च के पहले ही स्थापित किए जायेंगे। यह ब्रांच अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा।

उन्होंने कहा कि 90 के दशक में नये बैंको की स्थापना हुई तो लगा कि पुराने बैंक बंद हो जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी 80% व्यवसायी अपना व्यापार पुराने बैकों के माधयम सें ही करते हैं। इसमें 27% एस०बी०आई० के माध्यम से हो रहा है। यह बैंक सभी नई तकनीक को पहले अपनाता है। बैंक की 20 हजार शाखाएँ और 45 हजार से ज्यादा एटीएम सेवा है। बैंक अब बिजनेस पत्राचार को भी अपना रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैंक की नि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा अब स्मार्ट फोन पर भी उपलब्ध है। यह सुविधा अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम में भी है। अन्य भाषाओं में शीघ्र शुरू करने की योजना है।

श्री सूद ने लोगों को मनी कार्ड का उपयोग करने की भी सलाह दी। दिसंबर तक पटना अंचल में 70 नई शाखाएँ खोली जायेंगी, अभी 1480 शाखाएँ कार्यरत हैं। यह बैंक बिहार में उन सभी सुविधाओं को उपलब्ध करायेगा जो किसी भी विकसित राज्य में है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत नौ लाख लोगों का खाता खोला गया है।

श्री सूद ने KYC (Know Your Customer) फार्मेट को संबंधित बैंक शाखाओं पर जाकर जमा करने का भी आग्रह किया।

मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि एस०बी०आई० ऋण-जमा अनुपात की विसंगतियों को दूर करने को प्रतिबद्ध है, परन्तु इसके लिए प्रदेश में बड़ी इकाईयों और भारी औद्योगिक उत्पादन इकाईयों का लगना आवश्यक है। बैंक ऋण आवेदनों के त्वरित निबटारे के लिए सहयोग करेगा।

एस०बी०आई० के महाप्रबंधक (नेटवर्क-I) श्री अभिजीत दत्ता ने कहा कि ग्राहकों की समस्याओं का निपटारा समय पर किया जाएगा। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने सदस्यों से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर चैम्बर सदस्य या ग्राहक उनसे मिलकर अपनी समस्याएँ बता सकते हैं।

संवाद के अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं श्री मोतीलाल खेतान, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा सहित चैम्बर के सदस्य एवं मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

महामंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

MEMORANDUM SUBMITTED TO SHRI AJIT SOOD, CHIEF GENERAL MANAGER, STATE BANK OF INDIA,PATNA ON 13-11-2014

At the outset, I extend my heartiest welcome to Shri Ajit Sood, Chief General Manager, State Bank of India, General Manager-I, SBI, who have come to the Chamber's premises for the first time and we express our gratitude to them for their kind gesture for coming to the Chamber. We also welcome other Senior Officers of the SBI present here. It is very kind on the part of CGM, SBI who has kindly provided opportunity to our members for interaction and we hope this interaction will be beneficial for both of us.

In this meeting we wish to bring few points before you for your kind consideration:-

1. *Since State Bank of India is having larger share in banking business of the State, maximum number of borrowers like to deal with SBI. It is, therefore, submitted that emphasis should be given for expeditious disposal of the loan applications so that CD ratio of the State could be enhanced up to a satisfactory level. The bank should declare its financing policy particularly for Steel Industry in Bihar, so that*

potential entrepreneurs could know the exact position of financing.

2. *Branches in semi-urban areas where the CD Ratio is low should be identified for intensive lending under SSI and priority Sector. Due publicity should be given for special nature of services rendered by the branches.*
3. *Norms of credit rating should be advised to the borrowers. It should be derived after discussion with the borrower.*
4. *Besides agriculture, industrial and priority sector, ample scope also exists to finance small establishments such as IT based service providing centers, tiny industries besides trade establishments, agro based industries, food processing industries and cold storages. Many Solar Power Generating Units are also coming in the State because it has been kept in thrust area of Industrial Policy of the Government. For adequate enhancement in CD Ratio, it is suggested that a proper survey should be made also by the Bank for meeting the financial requirements of different sectors.*
5. *We would also like to bring to your kind notice that in cash credit limit of even less than one crore besides prime securities, other securities such as immovable property, pledge of fixed deposit and third party guarantor are being insisted by the Bank, which is even exempted by RBI. Hence, SBI should not insist for such collateral security or third party guarantee.*
6. *The higher processing fee discourages the borrowers i.e. entrepreneurs from taking loan facility from Bank, which ultimately affects the industrialization of the State. The SBI charges processing fee for Working Capital Loan every year which needs to be rationalized. Moreover, the processing fee, which is charged on Working Capital Loan is also charged on the non-fund based facilities like bank guarantee, which does not appear to be proper and this is required to be looked into.*
7. *The Bank takes legal opinion for the title examination of the immovable assets from two experts, which is got mortgaged by the bank and the bank realizes the legal fee of both the experts from the customer, which is not proper. The bank should bear the legal fee of at least one expert. Similarly, in case of the valuation of the immovable assets, the bank takes the opinion of the two valuers and again the bank realizes the charges of both the valuers from the customer. This is also not proper. The bank should bear the charge of at least one valuer.*
8. *We have been given to understand by our constituent that even after payment of full and final amount in compliance of the compromise reached between SBI & the Customer, the documents relating to assets submitted as securities are not returned to the customer even after expiry of many months. This should not happen.*
9. *The bank should install a Multipurpose Kiosk at SBI New Market Branch located near Ashok Cinema, Budha Marg, Patna. Moreover, in New Market Branch of the SBI due to lack of staff and due to excess crowd of the customers, the customers have to face a lot of difficulties and they have to be in queue for long period even for small works like updating of passbook, transfer of fund etc. and when the turn of a customer comes, unfortunately, either the link goes off or the printer goes out of order. This compounds the difficulties of the customers and they have to go many times to the bank even for small jobs.*
10. *Sometimes the cheques of the customers are returned by the SBI on account of non-uploading of the signature of the customer in their system and sometimes due to not updating the signatures of the customers. This causes unnecessary difficulties and embarrassment to the customers.*
11. *The bank realises interest during the pre-production period and for the gestation period also. The Units is not in a position to pay the interest in the gestation period and becomes defaulter with the bank. As soon as the unit become defaulter many problems start and sometimes the unit gets sick in the pre-production stage itself. Therefore, the bank should not insist for payment of interest during pre-production stage and interest accruing in the pre-production stage should be capitalized and should be made a part of the project cost, so that the unit is not required to pay interest in the pre-production stage.*
12. *The SBI should open a branch at Madhvapur (Madhubani) Bihar Madhvapur is a very old & reputed business centre, having College, High School, Hospital, Police Station, Agriculture farm and other private institution. The nearest branch of State Bank of India is located at Saharghat, which is around 13 KM away from Madhvapur. This is causing immense difficulties to businessmen, salaried people and pensioners besides general residents of the area. In view of the above, we request you to please look into the matter and do the needful, so that a branch of your esteemed Bank may be opened at Madhvapur at an early date.*
13. *The Nirmali Branch of the SBI is located at one and half kilometer from the main business place and this causes a lot of difficulties to the customers particularly in carrying cash to the bank or in bringing the cash from the bank to their business place. A few unpleasant events have already taken place due to transfer of the bank branch to a distant place. Hence, there is an immediate need to open either a new branch or an extension counter in the main business place. Hence, the Nirmali Chamber of Commerce had requested for the same. The bank is requested to look into the matter and solve the problem.*
14. *We would also like to draw your kind attention that in past, at the time of need of social responsibility and natural calamities, the Bihar Chamber of Commerce & Industries and the State Bank of India have always extended their generous support to the needy jointly. We wish to state that in past several EDP Programme have been organized by BCCI jointly with SBI. We intend to organize EDP Programme in future also jointly with the support of SBI.*

Thanking all of you present here.

चैम्बर ने रेल मंत्री एवं बिहार में सभी सांसदों एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बिहार में रेलवे रैक्स एवं रेलवे साईडिंग की कमी से हो रही असुविधाओं के संबंध में विस्तृत पत्र भेजा था।

उसी के प्रत्युत्तर में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने माननीय रेलमंत्री, भारत सरकार को पत्र लिखा है जिसकी प्रति चैम्बर को भी प्रेषित की गई है जिसे सदस्यों के सूचनार्थ नीचे उद्धृत किया जा रहा है।

नीतीश कुमार
पूर्व मुख्यमंत्री
बिहार

बिहार सरकार

आवास: 7, सर्कुलर रोड
(कौटिल्य मार्ग), पटना
पटना-800001

पत्रांक : 1004/14 (अ०)   दिनांक : 12.11.2014

Dear Shri Suresh Prabhu Ji,

Please find enclosed herewith letter no.677 dated 28.10.2014 from Shri P.K. Agrawal, President, Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001 regarding delay of over two months in placement of rakes booked for destinations in the state of Bihar from different locations outside Bihar, whereas for other destinations of outside Bihar, rakes are being placed within short time. It is due to acute shortage of goods siding in state of Bihar.

It would not be out of place to mention here that this delay causes scarcity of different commodities in this region and all sections of society suffer undue hardship as it creates shortage of essential goods and artificial price rise.

I would like to request you that additional new rake siding in sufficient numbers be provided in the state of Bihar to enable placement of rakes for transport of goods without delay. This will contribute to growth in revenue of Indian Railway and also contribute to the economic development of this region as well as our country.

With regards,

Encl: As above.

Yours sincerely,

(Nitish Kumar)

Shri Suresh Prabhu,
Hon'ble Railway Minister,
Govt. of India,
Rail Bhawan,
NEW DELHI – 110 001

Copy forworded to Shri P.K. Agrawal, President, Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001.

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन वर्मा को भावभीनी विदाई

बिहार सरकार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नवीन वर्मा, भा०प्र०से० का स्थानान्तरण अपर सचिव, रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (RAW) भारत सरकार के पद पर हुआ है। उनके स्थानान्तरण पर भावभीनी विदाई दी गई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने श्री वर्मा के इस स्थानान्तरण पर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर श्री व्यास जी, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा आपदा प्रबंधन, बिहार सरकार तथा श्री राजेश गुप्ता, प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार भी उपस्थित थे।

श्री नवीन वर्मा ने बिहार के अपने कार्यकाल में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के महत्वपूर्ण योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।

इस अवसर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका, चेयरमैन, वैट सब कमिटि श्री नवीन कुमार मोटानी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता एवं कार्यकारीणी सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद भी उपस्थित थे।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बाढ़ और कांटी थर्मल पावर का उद्घाटन किया
सूबे में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की

बिहार को 500 मेगावाट और बिजली

केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने बिहार में चार हजार मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है। शनिवार दिनांक 15.11.2014 को मुजफ्फपुर की कांटी और पटना के बाढ़ थर्मल पावर का उद्घाटन करने के क्रम में मंत्री ने यह घोषणा की। कांटी की दूसरी इकाई से 110 मेगावाट तो बाढ़ थर्मल पावर में स्टेज दो की पहली यूनिट से 660 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। कुल 770 मेगावाट में से बिहार को लगभग 500 मेगावाट बिजली मिलेगी।

मुजफ्फरपुर के समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कांटी थर्मल पावर का नाम पूर्व सांसद जॉर्ज फर्नांडीस के नाम पर रखने की घोषणा की। कहा कि कांटी की 195 मेगावाट की दो अन्य इकाइयों से साल भर के भीतर उत्पादन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दादरी से बिहार को 261 मेगावाट और बिजली मिलेगी। दादरी से अभी बिहार को 200 मेगावाट बिजली मिलती है। खेती को किसानों के लिए अलग से फीडर बनेगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लगे 10 व 25 केवीए के ट्रांसफॉर्मर को इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम से बदला जाएगा।

4 साल में जरूरत के अनुसार बिहार में बिजली उत्पादन : गोयल

पीयूष गोयल ने कहा कि अगले चार सालों में जरूरत के अनुसार बिहार में बिजली का उत्पादन होने लगेगा। कांटी व बाढ़ थर्मल पावर से उत्पादन होने के साथ ही उस दिशा में काम शुरू हो गया है। उन्होंने दिल्ली जाने के क्रम में स्टेट हैंगर पर पत्रकारों से कहा कि बाढ़ की सभी इकाइयां चालू हो जाएंगी और 3300 मेगावाट बिजली उत्पादित होने लगेगी। सुपौल के डगमारा में लंबित 132 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना की शीघ्र ही मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने इंदिरा आवास में लाभुकों की संख्या कम किए जाने पर कहा कि मौजूदा सरकार हर गरीब के लिए पक्का मकान बनाएगी।

बाढ़ थर्मल पावर के शुरू होते ही बिहार का केंद्रीय कोटा बढ़ा

बाढ़ थर्मल पावर व दादरी से बिजली मिलते ही बिहार के केंद्रीय कोटे में वृद्धि हो गई है। अब तक बिहार का केंद्रीय सेक्टर 2149 मेगावाट था। बाढ़ से 660 मेगावाट में से बिहार को लगभग 400 मेगावाट बिजली मिलेगी। वही, 14 नवंबर की देर रात से दादरी प्लांट से बिहार को 261 मेगावाट बिजली मिलने लगी। कांटी से अब बिहार को 220 मेगावाट बिजली मिलेगी। कमलांगा से औसतन 200 मेगावार बिजली बिहार को मिलती है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय कोटा से अगर 2400 मेगावाट तक भी बिजली मिली तो बिहार सरकार को बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं होगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.11.2014)**

110
मेगावाट बिजली उत्पादित होगी कांटी की दूसरी इकाई से

660
मेगावाट बिजली बनेगी बाढ़ के स्टेज दो की पहली यूनिट से

बिजली की दैनिक स्थिति

आवश्यकता	3500 मेगावाट
केंद्रीय कोटा	2810 मेगावाट
कमलांगा प्लांट	260 मेगावाट
हर रोज खरीद	400–700 मेगावाट
उपलब्धता	2300–2600 मेगावाट

बिहार को नहीं मिल रहा बिजली में वाजिब हक

बिहार को बिजली में वाजिब हक नहीं मिल रहा है। केंद्रीय कोटा से आवंटित पूरी बिजली नहीं मिल रही है। कई परियोजनाओं को कोल लिंकेज का इंतजार है। बीआरजीएफ (बैकवर्ड रीजन्स ग्रान्ट फंड) में तीन हजार करोड़ का बकाया है। दिनांक 15.11.2014 को बाढ़ व कांटी थर्मल पॉवर का उद्घाटन करने आ रहे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल के समक्ष बिहार एक बार फिर अपनी आवाज उठाएगा।

बिहार का केंद्रीय कोटा 2149 मेगावाट है। इसमें औसतन 1400 मेगावाट बिजली मिलने के कारण उसे बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। केंद्र सरकार के नियमानुसार कहलगांव प्लांट से 1170 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए। पर, यहां स्टेज एक में 840 मेगावाट में से 362 तो स्टेज दो में 1500 मेगावाट में से मात्र 98 मेगावाट बिजली मिलती है। बाढ़ और दादरी प्लांट से भी बिजली नहीं मिल रही है। भूटान और नेपाल में चल रही परियोजनाओं से भी बिजली की मांग की गई है।

नाइंसाफी : • कहलगांव थर्मल पावर से आधी बिजली भी नही • भूटान से बिजली मिलने के प्रस्ताव पर पहल नहीं • कई परियोजनाओं के लिए कोल लिंकेज मिलनी है बाकी • बीआरजीएफ में करोड़ों रुपए की राशि नहीं मिली है • भूटान व नेपाल में चल रही योजनाओं से भी बिजली की मांग • **2149** मेगावाट है बिहार का केंद्रीय कोटा में • **1400** मेगावाट औसतन मिल पाता है राज्य को • **144** यूनिट प्रति व्यक्ति व्यक्ति सालाना बिजली खपत है राज्य में • **917** यूनिट प्रति व्यक्ति सालाना बिजली खपत है देश में। **(साभार : हिन्दुस्तान, 15.11.2014)**

बिजली पर नीतीश की भीष्म प्रतिज्ञा पूरी : सीएम

9 वर्षों में 600 से 2800 मेगावाट पहुंचे

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 2015 तक बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की, लेकिन फर्क तो अभी ही दिखने लगा है। हम पिछले 9 वर्षों में 600 मेगावाट से 2800 मेगावाट तक पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पावर होल्डिंग कंपनी की स्थापना के दो वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 927 करोड़ रुपए की बिजली योजनाओं का शिलान्यास किया।

(साभार : दैनिक भास्कर, 2.11.2014)

बैंकों की हड़ताल के कारण पटना के 707 बैंकों में लटके ताले, एटीएम भी बंद

10वां द्विपक्षीय वेतन समझौता लागू करने को लेकर मंगलवार 12.11.2014 को राजधानी के सभी सरकारी बैंकों में ताला लटका रहा। यहां के 707 बैंकों में कारोबार ठप रहा। अनिवार्य जगहों को छोड़कर अधिकतर एटीएम भी बंद रहे। बैंक बंद रहने से उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों को काफी परेशानी हुई।

सभी बड़े बाजारों में बिक्री प्रभावित : हड़ताल से थोक व्यापारियों का बिहार में लगभग 30 प्रतिशत का कारोबार प्रभावित हुआ है। हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, पटना मार्केट, गोविंद मित्रा रोड, खजांची रोड, न्यू मार्केट, दलदली सहित सभी बड़े बाजारों में बिक्री घट गयी। बिक्री में कमी होने से राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।

"बैंकों में हड़ताल से समस्या का समाधान नहीं होता। इससे अरबों रुपए का कारोबार चौपट हो जाता है। इससे आम लोगों को भी परेशानी होती है। सरकार एवं बैंक यूनियनों को मिलजुल कर बीच का रास्ता निकालना चाहिए।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.11.2014)

जमा कर सकेंगे एडवांस बिल

बिजली उपभोक्ताओं को विनियामक आयोग ने दी सुविधा

बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी को उपभोक्ताओं से एडवांस राशि जमा लेने की इजाजत दे दी है। उपभोक्ता अब रेगुलर मासिक बिजली बिल के विरुद्ध एडवांस राशि जमा कर सकते हैं। इससे कनेक्शन कटने का भय नहीं रहेगा। आयोग ने एडवांस राशि जमा लेने के लिए न्यूनतम दो हजार निर्धारित किया है। इससे कम राशि जमा नहीं होगी। एडवांस राशि पर छह फीसदी ब्याज भी मिलेगा। कुटीर ज्योति से लेकर हाइ टेंशन उपभोक्ताओं को एडवांस राशि जमा करने की सुविधा दी गयी है। उल्लेखनीय है कि एडवांस राशि जमा लेने का निर्णय नॉर्थ व साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी ने लिया था।

इससे लिए बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति देने के लिए 21 फरवरी, 2014 को पिटीशन दायर किया था। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं के लिए पांच हजार रुपये एडवांस निर्धारित किया था। कंपनी के पिटीशन पर आयोग ने जन सुनवाई की इसमें बिजली उपभोक्ताओं सहित अन्य स्टॉक हॉल्डर से विचार लिया गया। आयोग द्वारा जन सुनवाई पूरी होने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया गया। आयोग ने पांच हजार के बदले दो हजार एडवांस राशि निर्धारित की है। बकाया बिजली बिल रहने पर एडवांस राशि जमा नहीं होगी।

(साभार : प्रभात खबर, 18.11.2014)

अनट्रेंड मीटर रीडर बढ़ा रहे बिजली बिल

राजधानी के अनट्रेंड मीटर रीडर उपाभोक्ताओं को गड़बड़ बिजली बिल का झटका दे रहे हैं। घरों व प्रतिष्ठानों में लगे विभिन्न तरह के मीटरों की कार्यप्रणाली नहीं जानने वाले ये मीटर रीडर अनाप-शनाप बिल थमा देते हैं। ऐसे में लोगों को बिल सुधरवाने के लिए पेसू के दफ्तरों की दौड़ लगानी पड़ती है। इधर पेसू के जीएम राजीव अमित ने इस तरह के बढ़े हुए बिजली बिलों की पूरी छानबीन की तो मामला पकड़ में आया।

यहां करें शिकायत : • पेसू का टोल फ्री नंबर : 18003456198 • पेसू हेल्पलाइन नंबर 0612-2280024, 0612-2280014

मिलें अपने-अपने इलाके के सहायक राजस्व अभियंता से : • डाकबंगला: 7763814062 • न्यू कैपिटल : 7763814093 • पाटलिपुत्र : 7763814106 • गर्दनीबाग : 7763814084 • दानापुर : 7763814071 • कंकड़बाग : 7763814147 • बांकीपुर : 7763814129 • राजेन्द्र नगर : 7763814173 • गुलजारबाग : 7763814138 • पटना सिटी : 7763814161

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.11.2014)

SBI GIVES BLUEPRINT FOR Rs. 50K - CR POWER FUND

India's largest lender, State Bank of India, has submitted details of the proposed power sector fund, which is likely to be set up with a corpus of Rs 50, 000 crore for reviving stalled power projects in the country. It will also help recover thousands of crores worth of banking sector funds that are stuck in such projects.

According to the concept paper worked out by SBI, a copy of which is available with HT, the fund would have 49% contribution investors from power sector PSUs, with the balance coming from banks and foreign.

(Details : H. T., 13.11.2014)

उपभोक्ता और उद्योगों को राहत की आस बढ़ी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की सस्ते कर्ज की जोरदार वकालत

आंकड़ों में घटती महंगाई और औद्योगिक उत्पादन में कमी के बीच उपभोक्ता और उद्योग दोनों के लिए सस्ते कर्ज की उम्मीद बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्याज दरों में कटौती की वकालत की तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस. एस. मुंदड़ा ने भी मौद्रिक नीति की समीक्षा में सभी कारकों को ध्यान में रखने की बात कहकर सकारात्मक संकेत दिया।

कतार में हैं ये आर्थिक सुधार : • **जीएसटी :** इससे देश में एकीकृत कर प्रणाली की शुरुआत होगी, जो अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। • **कहां तक पहुँची बात :** वित्त मंत्री जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले इसके मसौदे की जानकारी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को देंगे। • **बीमा संशोधन विधेयक :** इसके आने से बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ेगी और घरेलू कंपनियों को पूंजी और विशेषज्ञता भी हासिल होगी। • **कहां तक पहुंची बात :** सरकार इसे लेकर प्रवर समिति के संपर्क में है। समिति विधेयक की समीक्षा कर रही है।

महंगाई और कर्ज : • **08** फीसदी है रेपो दर, जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण मुहैया कराता है • **5.52** फीसदी रही खुदरा महंगाई दर अक्टूबर महीने में • **1.77** फीसदी के स्तर पर रही थोक महंगाई दर अक्टूबर में।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.11.2014)

नई औद्योगिक नीति की मध्यावधि समीक्षा

राज्य सरकार ने 2011 में अपनी नई औद्योगिक नीति लागू की थी। पिछले साल निवेशकों की घटती तादाद से राज्य सरकार ने इसकी मध्यावधि समीक्षा का फैसला लिया था। सूत्रों के मुताबिक इस नीति की समीक्षा का काम पूरा हो चुका है, लेकिन राज्य कैबिनेट से अब तक इसे मंजूरी नहीं मिली है।

इस बारे में सूत्रों ने बताया, 'इस बारे में काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके तरह हमने उद्यमियों के प्रक्रिया में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने के कदम और उद्यमियों के अनुदान में इजाफे का प्रस्ताव रखा है। बस कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।' सूत्रों के मुताबिक इस बारे में कैबिनेट को दो बार प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से इसे अभी तक राज्य सरकार की सहमति नहीं मिल सकी है। इसके तहत राज्य सरकार ने सबसे पहले तो पूंजीगत अनुदान की सीमा में इजाफा करने का फैसला लिया है। पहले राज्य में निवेशकों को 75 लाख रुपये तक का अनुदान मिलता था। हालांकि, अब राज्य सरकार ने इसकी सीमा को दो करोड़ रुपये तक करने का फैसला लिया है। साथ ही, राज्य सरकार अब पुरानी इकाइयों के आधुनिकीकरण पर भी निवेशकों को अनुदान देने जा रही है।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.11.2014)

भूल सुधार

12 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित बुलेटीन संख्या 16 में प्रथम पृष्ठ पर नीचे वाले फोटोग्राफ के कैप्सन में डी.आई.जी. श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा की जगह भूलवश उपेन्द्र कुशवाहा छप गया है। सदस्यों से आग्रह है कि डी.आई.जी. के नाम को कृपया सुधार कर पढ़ें। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।

बिहार सरकार सूचना–प्रौद्योगिकी नीति में करेगी बदलाव

बिहार सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनी आईटी नीति में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए नई रियायतों के साथ-साथ अपने अनुदान को भी युक्तिसंगत बनाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। इस समीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार अब बिहार में आईटी उद्योग को आकर्षित करने की सोच रही है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.11.2014)**

युवाओं के प्रशिक्षण पर रहेगा जोर

बिहार सरकार ने राज्य में एक लाख से ज्यादा गरीब युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ हाथ मिलाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने एनआईआईटी, अपोलो हॉस्पिटल्स और कैफे कॉफी डे सहित 41 कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। इस काम में राज्य सरकार करीब 112 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की तैयारी : • बिहार सरकार ने वर्ष 2017 तक लगभग एक करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का रखा है लक्ष्य • महिलाओं और लड़कियों के प्रशिक्षण को खास तौर पर दिया जाएगा बढ़ावा • सरकार ने निजी क्षेत्र की एजेंसियों के साथ मिलाया हाथ। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 18.11.2014)**

सूबे में निवेश की राह आसान करेंगी निगरानी समितियां

राज्य में बड़े उद्योगों में निवेश की राह जिलों की निगरानी समितियाँ आसान करेंगी। राज्य सरकार ने जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण की समीक्षा के लिए निगरानी समिति का गठन किया है। यह समिति प्रत्येक जिले में बड़े उद्योगों के प्रस्ताव व अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी। उनके निर्माण में आने वाली बाधाओं को विभागों के समन्वय से दूर किया जाएगा।

निवेशक होंगे आकर्षित : निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने को लेकर तैयारी की गई है। जिलास्तरीय निगरानी समिति जिलों में शुरू होने वाली केंद्र, राज्य व निजी क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं की समान रूप से समीक्षा करेगी, ताकि उन्हें निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके। योजना एवं विकास विभाग के निर्देश पर गठित जिलास्तरीय समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे।

समन्वय बनाने का निर्देश : मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक कर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रमंडलीय आयुक्त अपनी मासिक समीक्षा बैठक में समिति के कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति समीक्षा करेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.11.2014)**

गंगा में गंदा पानी डाला तो बंद होगी फैक्ट्री

पटना में अगले दो साल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने को प्रदूषण बोर्ड ने बनाया एक्शन प्लान

गंगा नदी को स्वच्छ व प्राणदायिनी बनाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने एक्शन प्लान बनाया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के प्रदूषण बोर्ड से पूछा था कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए क्या योजना है? प्रदूषण बोर्ड ने कार्ययोजना बनाकर सीपीबीसी को भेज दिया है। इसके तहत राज्य में जो भी फैक्ट्री या उद्योग हैं, उनके निकलने वाला गंदा पानी गंगा में नहीं डाल सकते हैं।

सभी उद्योगों व फैक्ट्रियों को सख्त हिदायत दी गई है कि 31 मार्च 2015 तक ऑनलाइन इंफ्लूएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर लें। जून 2016 के बाद इन फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में नहीं डालने की समय सीमा तय कर दी गयी है। खास बात यह है कि फैक्ट्रियों में जो सिस्टम लगनी है, उससे बिहार प्रदूषण बोर्ड ऑनलाइन जुड़ा रहेगा। प्रतिदिन की मॉनिटरिंग कर सीपीसीबी को रिपोर्ट भेजनी है ताकि यह पता चल सके कि जिन उद्योगों में यह सिस्टम लगा है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। प्रदूषण बोर्ड इस बात की भी मॉनिटरिंग करेगा कि किस उद्योग या फैक्ट्री वालों ने सिस्टम नहीं लगाया है। सिस्टम नहीं लगाने पर फैक्ट्री बंद की जाएगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 15.11.2014)**

50 एकड़ में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर

केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने पटना में मांगी जमीन

केंद्रीय सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री रविशंकार प्रसाद ने कहा कि पटना में 50 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार जमीन दे तो केंद्र 50 करोड़ की लागत से इसका निर्माण जल्द शुरू कराएगा। ताकि एलजी और सैमसंग जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कपनियां यहां निर्माण इकाई लगा सके। उन्होंने कहा कि क्लस्टर से जुड़कर पूंजी निवेश करने वाले को 100 में 25 रुपए का अनुदान भी केंद्र देगा।

श्री प्रसाद ने कहा कि दरभंगा और भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेवनोलॉजी पार्क खुलेगा। उन्होंने इसके लिए दरभंगा व भागलपुर में राज्य सरकार से जमीन मांगी और मौके पर ही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दोनों जगहों के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में जमीन देने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रावैधिकी संस्थान (नाइलेट) का सेंटर बक्सर और मुजफ्फरपुर में खुलेगा।

(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 9.11.2014)

राइस मिलरों की समस्या सुलझायेंगे मुख्यमंत्री

चावल मिल मालिकों और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में जहानाबाद, गया एवं बिहार के सुदूर जिलों से आये हुये लोगों की समस्याओं को सुना। राम कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राइस मिलर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को बिहार के राइस मिलों से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चावल मिल मालिकों एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। **(राष्ट्रीय सहारा, 15.11.2014)**

राज्य में अगले वर्ष कई तरह के टैक्स बढ़ेंगे

वित्त विभाग ने सरकारी विभागों से टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव मांगा

राज्य में अगले वर्ष विभिन्न तरह के टैक्स बढ़ेंगे। विकास कार्यों को जारी रखने के लिए राज्य सरकार टैक्सों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से नए वित्त वर्ष में टैक्स या शुल्क में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव मांगा है। जिन मामलों में विधि विभाग की राय ली जानी जरूरी हो, उसे भी साफ करने का निर्देश दिया है।

पूरे वित्तीय वर्ष में हो सकेगी राजस्व की प्राप्ति : वित्त विभाग के अनुसार बजट के साथ ही वित्त विधेयक भी पेश किया जाता है। वित्त विधेयक बजट के साथ पारित किए जाने से उसे एक अप्रैल से लागू किया जा सकता है। इससे लाभ यह होगा कि संबंधित कर-राजस्व व गैर कर-राजस्वों में प्रस्तावित बढ़ोतरी पूरे वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो सकेगी।

टैक्सों के बारे में मांगी अद्यतन जानकारी : वित्त विभाग ने विभिन्न के विभागों के अधीन कर-राजस्व एवं गैर कर-रांजस्व में वर्तमान में किस-किस दर से तथा किस तिथि से राशि लागू की गयी है। इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा है। अगर राशि में बढ़ोतरी नहीं करनी हो तो इसे भी स्पष्ट करने को कहा गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.11.2014)**

इन्कम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया अब और होगी आसान

इन्कमटैकस रिफंड प्रक्रिया और आसान होगी। आयकर विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभाग की योजना है कि आयकरदाताओं की सुविधा के लिए पांच और प्रोसेसिंग सेन्टर खोले जाएं। इसमें पुणे, गुडगांव, कोलकाता, चेन्नई शामिल हैं। गाजियाबाद में टीडीएस का प्रोसेसिंग सेन्टर खोला गया है। करदाताओं के रिफंड का भुगतान शीघ्र होगा। अभी आयकरदाता जो भी रिफंड फाइल करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग बेंगलुरू में हो रही है। करदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रोसेसिंग में काफी लंबा वक्त लग रहा है। इसलिए विभाग ने पांच जगहों पर प्रोसेसिंग सेन्टर खोलने का प्रस्ताव रखा है।

इधर आयकर विभाग की धीमी प्रोसेसिंग के कारण लाखों करदाताओं के रिफंड का भुगतान नहीं हो पाया है। रिफंड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रिफंड भुगतान के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। बोर्ड ने सभी रीजिनल हेड को निर्देश दिया था कि आयकरदाताओं के

बकाए रिफंड का भुगतान यथाशीघ्र किया जाए। बोर्ड ने आयकरदाताओं के रिटर्न व टीडीएस का वेरिफिकेशन कर रिफंड राशि लौटाने का निर्देश दिया था लेकिन एक-एक आयकरदाता को 3-4 वर्षों के बाद भी रिफंड नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड भुगतान में कठिनाई हो रही है। इस मामले में आयकर आयुक्त प्रशांत भूषण ने कहा कि बेंगलुरु के अतिरिक्त पांच और जगहों पर प्रोसेसिंग सेन्टर खोलने का प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है ताकि आयकरदाताओं की शीघ्र रिफंड का भुगतान हो सके। **(हिन्दुस्तान, 14.11.2014)**

भारत सरकार केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर आयुक्त कार्यालय पटना से प्राप्त पत्र दिनांक 12.11.2014 के अनुसार बिहार के कार्यालयों में निम्नानुसार अवकाश रहेगा जो सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है:-

सूचना (दिनांक - 12.11.2014)

मुख्य आयकर आयुक्त (सी. सी. ए.) पटना सह-अध्यक्ष, केन्द्र सरकार कल्याण समन्वय समिति पटना द्वारा प्रेषित पत्रांक F.No. CCIT (CCA) PAT./Welfare/ Holidays/2014-15/9895-9650 दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के अनुसरण बिहार राज्य स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में निम्न संलग्नित परिशिष्ट 'क' में वर्णित छुट्टियाँ मनायी जाएंगी।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारी वर्ष में दो (2) प्रतिबंधित छुट्टी भी ले सकेंगे जिसकी सूची नीचे परिशिष्ट 'ख' में संलग्नित है:-

परिशिष्ट 'क'
वर्ष 2015 के लिए राजपत्रित छुट्टियों की सूची

	छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह का दिन
1	ईद-ए-मिलाद	04.01.2015	रविवार
2	गणतंत्र दिवस	26.01.2015	सोमवार
3	होली	06.03.2015	शुक्रवार
4	महावीर जयंती	02.04.2015	गुरुवार
5	गुड फाईडे	03.04.2015	शुक्रवार
6	बुद्ध पूर्णिमा	04.05.2015	सोमवार
7	ईद-उल-फितर	18.07.2015	शनिवार
8	स्वतंत्रता दिवस	15.08.2015	शनिवार
9	ईद उल जूहा (बकरीद)	25.09.2015	शुक्रवार
10	महात्मा गांधी जयंती	02.10.2015	शुक्रवार
11	दशहरा (महाअष्टमी)	21.10.2015	बुधवार
12	दशहरा (विजयादशमी)	22.10.2015	गुरुवार
13	मुहर्रम	24.10.2015	शनिवार
14	दीपावली	11.11.2015	बुधवार
15	छठ पूजा	17.11.2015	मंगलवार
16	गुरु नानक जयंती	25.11.2015	बुधवार
*	ईद-ए-मिलाद	24.12.2015	गुरुवार
18	क्रिसमस डे	25.12.2015	शुक्रवार

*मिलाद-उन-नवी या ईद-ए-मिलाद (मोहम्मद साहब का जन्मदिन) वर्ष 2015 में दो बार पर रहा है।

परिशिष्ट 'ख'
वर्ष 2015 के लिए प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची

	छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह का दिन
1	नववर्ष उत्सव	01.01.2015	गुरुवार
2	मकर सक्रांति	14.01.2015	बुधवार
3	पोंगल	15.01.2015	गुरुवार
4	श्री पंचमी/वसंत पंचमी	24.01.2015	शनिवार
5	गुरु रविदास जयंती	03.02.2015	मंगलवार
6	स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती	14.02.2015	शनिवार
7	महाशिवरात्रि	17.02.2015	मंगलवार
8	शिवाजी जंयती	19.02.2015	गुरुवार
9	होलिकादहन	05.03.2015	गुरुवार
10	चैत्र शुक्लादी/गुडी पर्व/ उगादी/चेटी चाँद)	21.03.2015	शनिवार
11	रामनवमी	28.03.2015	शनिवार
12	इस्टर रविवार	05.04.2015	रविवार
13	वैशाखी/विशु/मसादी	14.04.2015	मंगलवार
14	वैशाखी (बंगाल) बहग बिहू (असम)	15.04.2015	बुधवार
15	हजरत अली साहेब का जन्म दिन	03.05.2015	रविवार
16	गुरु रवीन्द्रनाथ जयंती	09.05.2015	शनिवार
17	जमात-उल-विदा	17.07.2015	शुक्रवार
18	रथ यात्रा	18.07.2015	शनिवार
19	पारसी नर्व वर्ष दिवस/नवरोज	18.08.2015	मंगलवार
20	ओणम	28.08.2015	शुक्रवार
21	रक्षा बंधन	29.08.2015	शनिवार
22	जन्माष्टमी	05.09.2015	शनिवार
23	विनायक चतुर्थी/गणेश चतुर्थी	17.09.2015	गुरुवार
24	महासप्तमी (अतिरिक्त)	20.10.2015	मंगलवार
25	महर्षि वाल्मिकी जयंती	27.10.2015	मंगलवार
26	कारका चतुर्थी (करवा चौथ)	30.10.2015	शुक्रवार
27	दीपावली (दक्षिण भारत)	10.11.2015	मंगलवार
28	नरक चतुर्दशी	10.11.2015	मंगलवार
29	गोवर्धन पूजा	12.11.2015	गुरुवार
30	भाई दूज	13.11.2015	शुक्रवार
31	प्रतिहार षष्ठी/सूर्या षष्ठी (छठ पूजा)	17.11.2015	मंगलवार
32	छठ पूजा का पारण	18.11.2015	बुधवार
33	गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस	24.11.2015	मंगलवार
34	चेहल्लुम	02.12.2015	बुधवार
35	क्रिसमस संध्या	24.12.2015	गुरूवार

जीएसटी की राह में अड़ंगा

- **शीतकालीन सत्र में जीएसटी विधेयक पेश होने की उम्मीद की लगा झटका**
- **राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में असहमति**

बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राह में अड़चनें बनी बनी हुई हैं। जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। राज्यों की मांग है कि इसे लागू करने के लिए सालाना कारोबार की सीमा 10 लाख रुपये रखी जाए। पेट्रो उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। राज्यों के अपने रुख पर कायम रहने के चलते जीएसटी के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने की उम्मीद को झटका लग सकता है। हालांकि राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी एक अप्रैल, 2016 से लागू होने की उम्मीद जताई है।

समिति के प्रमुख और जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथेर ने कहा कि केंद्र ने उन्हें पत्र लिखकर जीएसटी लागू करने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है। राज्यों ने अगस्त में यह तय किया था कि जीएसटी के लिए कारोबार की सीमा 10 लाख रूपये रखी जाए। इसके बाद केंद्र ने सितंबर में एक पत्र लिखकर कहा कि जीएसटी लागू करने की सीमा के संबंध में राज्यों के फैसले की समीक्षा की जाए।

यह भी सुझाव दिया कि अगर यह सीमा 25 लाख रुपये नहीं हो सकती तो कम से कम इतना किया जाए कि इसे 10 लाख रुपये से थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। राथेर ने कहा कि अंतत: राज्यों ने तय किया है कि जीएसटी लागू होने की सीमा 10 लाख रुपये ही रखी जाए। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.11.2014)**

देश में एक बैंक में आपका अब एक खाता ही खुलेगा

आरबीआई के निर्देश पर अमल, दूसरे बैंकों में खुल सकते हैं खाते

अब एक बैंक में आपका एक ही खाता खुलेगा। चाहे दूसरा खाता किसी अन्य राज्य में ही क्यों न खोला जा रहा हो जिन ग्राहकों का किसी बैंक की एक से अधिक शाखाओं में खाता है, तो आने वाले दिनों में उसे मर्ज कर दिया जाएगा।

यह ग्राहक पर निर्भर करेगा कि वह किस शाखा से जुड़ा रहना चाहता है। एफडी के लिए भी ग्राहकों का पैन नंबर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। एक से अधिक

शाखाओं में एक पैन को स्वीकार नहीं किया जा रहा। एसबीआई की शाखाओं में एक पैन नंबर का हवाला देकर कई को लौटाया गया।

बैंक अधिकारी आरबीआई के नियमों का हवाला दे रहे हैं। हालांकि, वे यह नहीं बता रहे कि यह नियम ज्वाइंट एकाउंट के ग्राहकों पर लागू नहीं होती। हालांकि कोई भी व्यक्ति अगर एक से अधिक बैंक में अपने खाते रखता है तो यह नियमत: सही है। आरबीआई, पटना के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि बैंक अपनी अलग-अलग शाखाओं में किसी एक व्यक्ति का एक से अधिक खाता खोलने से मना कर सकता है। लेकिन दूसरे बैंकों में खाता रहने पर भी उन्हें खाता खोलना होगा।

एसबीआई ने लागू किया आरबीआई का निर्देश : एसबीआई ने सबसे पहले आरबीआई के नियम को लागू किया है। इस वर्ष मई में स्टेट बैंक मुख्यालय ने अपनी सभी शाखाओं को इस बाबत निर्देश जारी किया था। आरबीआई की यह कवायद कालेधन की मूवमेंट रोकने को लेकर है। बैंकों में जमा राशि से जिनकी वार्षिक आमदनी 10 हजार से अधिक होती है, उनपर टीडीएस लगता है। इसी से बचने के लिए लोग कई एकाउंट रखते हैं। अब सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को ट्रेस किया जाए और उनकी कुल जमा राशि को एक एकाउंट आईडेंटिटी से फॉलो किया जा सके।

पैन कार्ड के बगैर भी खुलता है खाता : अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो भी बैंक उसका खाता खोलने को बाध्य है। बस इसके लिए फार्म 60 भरना पड़ता है। फार्म 60 के माध्यम से डिक्लेरेशन लिया जाता है कि व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है। नाम न बताने की शर्त पर एक बैंक अधिकारी ने बताया कि कई बैंक नए खातों का लोड नहीं लेना चाहते और अघोषित रूप से खाते खोलने की प्रक्रिया रोक दी है।

हर ग्राहक को यूनिक आईडी : एसबीआई ने हर ग्राहक को यूनिक आईडी दी है। सॉफ्टवेयर में पैन नंबर डालते ही पता चल जाता है कि इस पैन का स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में खाता है या नहीं। 70% बैंकों में ग्राहकों की पैन हिस्ट्री फॉलो की जा रही है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 17.11.2014)

गैस उपभोक्ताओं को देना होगा बैंक एकाउंट नंबर

गैस उपभोक्ताओं को एक बार फिर अपने बारे में गैस कंपनी को जानकारी देनी होगी खासकर जिसके नाम से गैस कनेक्शन है, उसका पता एवं बैंक एकाउंट देना होगा। 20 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच उपभोक्ताओं से नाम एवं एकाउंट नंबर लिए जा सकते हैं।

इस काम के लिए जल्द ही गैस एजेंसियों में फॉर्म भेज दिया जाएगा। इसी बैंक खाते की मदद से एलपीजी ग्राहकों को गैस सब्सिडी का रुपया सीधे एकाउंट में जाएगा। जो गैस उपभोक्ता 31 दिसंबर 2014 से पहले अपना बैंक खाता नहीं देंगे, उन्हें बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मिलेगा।

क्यों देना होगा एकाउंट नंबर : 15 नवंबर से देश के 54 जिलों में डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफट ट्रांसफर फॉर एलपीजी) योजना लागू की जा रही है। इसके तहत गैस सब्सिडी का पैसा सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जाएगा। देश के शेष जिलों में यह योजना पहली जनवरी 2015 से लागू होगी।

कैसे होगा काम : गैस एजेंसियाँ अपने उपभोक्ताओं से नाम, पता एवं खाता नंबर एक फॉर्म पर भरवाकर तेल कंपनियों को भेजेगी। तेल कंपनियां उस फॉर्म को बैंक में भेजकर नाम एवं खाता नंबर की जांच करेंगी। यहां से खाता नंबर सीधे कंपनी के सर्वर में चला जाएगा। यदि खाता नंबर सही नहीं होगा, तो उसे दोबारा गैस एजेंसी में भेज दिया जाएगा। यहां फिर से गैस एजेंसी अपने ग्राहक से पूरी जांच कर तेल कंपनी को कॉर्म भेजेगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.11.2014)

कच्चे माल पर 4% इंट्री टैक्स खत्म करे बिहार

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार कच्चे माल पर लगने वाले चार फीसदी इंट्री टैक्स को खत्म करे। झारखंड ने इस तरह के टैक्स को खत्म कर दिया है। इंट्री टैक्स की वजह से बिहार के उद्यमियों के उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। इस कारण वे प्रतिस्पर्द्धा से बाहर हो जाते हैं।

बोले गिरिराज : • मुजफ्फरपुर में लीची-लहठी और पटना में प्रिंटिंग क्लस्टर बनाएगी केंद्र सरकार • सुगांधित पौधों के व्यावसायिक उपयोग की ट्रेनिंग के लिए बिहटा में बनेगा संस्थान।

परेव पीतल उद्योग पर ऊर्जा सचिव से बात की : गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ऐसा कानून लाए जिसमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक इकाइयों से अनिवार्य रूप से बीस प्रतिशत की खरीदारी हो। परेव में पीतल के बर्तन बनाने वाले उद्यमियों के बीच बकाया भुगतान को लेकर कटी बिजली के संबंध में उन्होंने ऊर्जा विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत से बात की है। सेटलमेंट को लेकर बात हुई है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.11.2014)

कर्ज पर हो उचित ब्याज दर

सुझाव : रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने वित्तीय संस्थानों को दी सलाह

रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने उपभोक्ता हितों के संरक्षण, छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने और उस पर ब्याज दरों की उचित सीमा तय करने के लिए देश के वित्तीय संस्थानों को सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा किसानों का उपलब्ध कराये गये ऋण की माफी योजना पर भी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने नाबार्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संबोधन में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों द्वारा बार-बार ऋण माफी से ऋण व्यवस्था में गड़बड़ होती है। अंतत: इससे ऋण बाजार खराब होता है।

माह के अंत तक खुलेगा भुगतान बैंक : रिजर्व बैंक छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए मानदंड तय करने के बाद इस महीने के आखिर तक आवेदन आमंत्रित करेगा। ये बैंक छोटे कारोबारियों और निम्न आयवर्ग के परिवारों की जरूरतें पूरी करेंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम-राजन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके साथ ही केंद्रीय बैंक अपनी नकदी प्रबंधन प्रणाली को भी बेहतर बनाने की योजना बना रहा है। राजन ने यह भी कहा कि अपनी जरूरतों के लिए छोटा- मोटा ऋण लेनेवालों की मनमानी ब्याज ऊंची दरों से सुरक्षा की जानी चाहिए।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 14.11.2014)

अब एटीएम के ज्यादा इस्तेमाल से कटेगी जेब

एसबीआई के बाद अब तीन अन्य बैंकों ने लिया फैसला

आरबीआई की ओर से फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन को लेकर निर्देश जारी करने के बाद देश के कई बैंकों ने भले ही तुरंत लागू नहीं किया था। लेकिन एसबीआई के लागू करने के बाद अब इसे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक जैसे बड़े बैंकों ने लागू करने का फैसला किया है। अब 1 दिसम्बर से एचडीएफसी और एक्सिस बैंक एटीएम से पांच बार फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा देंगे। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 20 रूपए और टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में तीन बार ही फ्री ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। यह नियम 6 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बंगलुरू और हैदराबाद में लागू होगा। वहीं यूनियन बैंक अपने ग्राहकों को महीने में 8 बार फ्री ट्रांजेक्शन्स की सुविधा देगा। इसके बाद वह हर ट्रांजेक्शन पर 15 रुपए का जार्ज और टैक्स वसूलेगा। साथ ही दूसरे बैंक के एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट महीने में 3 बार ही होगी। गौरतलब है कि पिछले महीने आरबीआई ने इसी संदर्भ में गाइडलाइंस जारी की थी।

(साभार : आई-नेक्स्ट, 14.11.2014)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296